(c) The economic reforms initiated by the Government have been based on wide ranging consultations with difference sections of society for securing the maximum possible consensus for our development strategy.

Evasion of Excise Duty Payment by Industrial Houses

4003. SHRI SATISH PRADHAN Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether there have been industries evading/avoiding payment of excise duties on a regular basis;

(b) if so, what are the details of such industries and the amount evaded during the last three years, yearwise and reasons thereof;

(c) whether Reliance Industries Limited has evaded/avoided payment of excise duty to the tune of crores of rupees; if so, what action Government propose to take against them;

(d) whether Government propose to amend the rules and impose 'payment first' dispute later policy in case of flimsy grounds, if so, what is its effective date and if not, what are the reasons therefor; and

(e) whether Government will contemplate to institute criminal proceedings against such industrial houses?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKHAR MURTHY): Cases of evasion of excise duty have been detected against various units from time to time.

(b) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(c) Show Cause Notices have been issued to M/s. Reliance Industries Ltd. over the years, for alleged evasion of excise duty to the tune of crores of rupees. Action under the Central Excise Act and Rules is being taken in these cases.

(d) Since it is not possible to define the term 'flimsy grounds', there is no move at present to amend the rules and impose 'payment first and dispute later' policy in such cases.

(e) Prosecution proceedings are launched against industrial houses in serious cases in accordance with provisions of the Central Excises & Salt Act, 1944 and rules made thereunder.

कर अपवंचन के बारे में संसद सदस्यों से प्राप्त शिकायतें

4004. **श्री राम सिंह राठवा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संसद सदस्यों से प्राप्त शिकायतों के आधार पर कर अपवंचन के संबंध में कोई सर्वेक्षण/जांच कराई है ;

(ख) इन शिकायतों के आधार पर कितने मूल्य के कर अपवंचन का पता चला है ; और

(ग) ऐसी शिकायतें किन-किन व्यक्तियों के विरुद्ध मिली हैं ?

वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जब कभी संसद सदस्यों द्वारा कर अपवंचन का कोई मामला सरकार के ध्यान में लाया जाता है तो सर्वेक्षण करके, तलाशी लेकर अथवा अन्य प्रकार की जांच-पड़ताल करके समुचित कार्यवाही की जाती है ।

(ख) आयकर की चोरी सर्वेक्षण, तलाशी तथा कर-निर्धारण की कार्यवाहियों आदि जैसी विभिन्न कार्यवाहियों के दौरान पकड़ी जाती है । इन विभिन्न कार्यवाहियों के दौरान पकड़ी गई कर की चोरी से संबंधित आंकड़े अलग-अलग नहीं रखे जाते हैं ।

(ग) वित्त वर्ष 1991-92 के दौरान प्राप्त हुई शिकायतों का ब्यौरा विवरण में दिया गया है ।

विवरण

क्रम संख्या	व्यक्ति/जिस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत की गई, उसका नाम
1	2
1.	मैसर्स रविन्द्र कुमार, मैसर्स रिद्धि सिद्धि टेक्सटाइल्स, बी०एम० अग्रवाल तथा अन्य बम्बई
2.	श्री हनुमान कालीवाडा प्रसाद
3.	प्रोग्रेसिव कंस्ट्रक्शन प्रा०लि०, हैदराबाद
4.	आई०टी० सी० लिमिटेड, कलकत्ता के वरिष्ठ कार्यपालक
5.	जालान परिवार, चावल मिल मालिक, उत्तर प्रदेश
6.	कच्छवा कोल्ड स्टोरेज के मालिक, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश
7.	लाटरी आर्गेनाइजर्स
8.	सहारनपुर, उत्तर प्रदेश के धर्म सिंह
9.	दिल्ली के श्री एच०सी० अरोड़ा की पुरस्कार याचिका ।
10.	डा० विजय कुमार दातला, प्रबन्ध निदेशक, बायोलोजिकल ई० लिमिटेड ।
11.	भोपाल के निर्मल चन्द जैन तथा अन्य
12.	बम्बई की मैसर्स गिल एण्ड कम्पनी
13.	बिहार के सर्वश्री लक्ष्मण प्रसाद तथा रमेश प्रसाद
14.	मैसर्स शक्ति ट्यूब्स लिमिटेड, बिहार
15.	पटना के डा० एन० प्रसाद
16.	पी०एस० जीयापुर, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश
17.	रामेश्वर दयाल गुप्त, सहायक लेखा-परीक्षक, जयपुर ।
18.	मध्य प्रदेश के सर्वश्री बदरूकेश्वानी तथा दरबारी लाल केश्वानी
19.	सर्वश्री सी० रामास्वामी तथा एम० पलानीसामी, मैसर्स शक्ति इन्टरप्राइजेज के भागीदार
20.	पी०के० दुबे, उप निदेशक, आयकर तथा एच०एन० घियाना, सहायक निदेशक, आयकर
21.	आर०के० सिंह, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड
22.	ग्रेटर कैलाश, नई दिल्ली तथा फरीदाबाद में कुछेक व्यक्तियों के संबंध में जांच-पड़ताल
23.	मुरारका इंजीनियरिंग वर्क्स
24.	उत्तर प्रदेश के एन०सी० चतुर्वेदी
25.	दिल्ली में वनस्पति तेल के व्यापारी
26.	बम्बई के प्रोफेसर बी० नाग
27.	परमानंथम तथा बी० देवराजन
28.	श्रीमती मित्रा तथा श्री दत्ता
29.	मैसर्स नीलगिरि इंजी० को०आप० सोसाइटी
30.	लाल जय दयाल डालमिया तथा परिवार
31.	रिलायन्स इण्डस्ट्रीज, बम्बई

Impact of rupee convertibility

4005. SHRI RAJNI RANJAN SAHU: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government have made any estimate of the total amount of dollars held back by exporters as on the 28th February, 1993; and

(b) what is the likely impact of such a large scale inflow of dollars on account of rupee convertibility?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. ABRAR AHMED): (a) No, Sir.

(b) The unification of exchange rate effected from March 1, 1993 is expected to result in a faster repatriation of export proceeds, augmented inflow of remittances and a diversion of funds from illegal channels These would take care of market demand for foreign exchange and ensure its stability.